शिक्षक - रवि शंकर राम, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 12-11-2020, वर्ग - MA-III

(3) औद्योगिक प्रन्यासों की व्यवस्था → औद्योगिक प्रशासन के विकेन्द्रीकरण हेतु औद्योगिक प्रन्यासों ~~के गठन की प्रक्रिया~~ की व्यवस्था की गई, जो वाणिज्यिक दृष्टि से स्वायत्तशासी इकाईयाँ थे। प्रन्यासों के गठन की प्रक्रिया जुलाई 1922 में आरंभ हुई। जून 1923 तक 478 प्रन्यास गठित हुए, जिनमें 354 उपक्रम सम्मिलित थे। इन प्रन्यासों को सरकार ने 'संघीय' 'प्रादेशिक' और 'स्थानीय' तीन श्रेणी में बांटते हुए क्रमशः सर्वोच्च, प्रादेशिक एवं स्थानीय आर्थिक परिषदों के नियंत्रण के रखा। समस्त प्रन्यासों में से 60 प्रतिशत संघीय, 15 प्रतिशत प्रादेशिक और 25 प्रतिशत स्थानीय थे। आधे से अधिक प्रन्यास लघु आकार के थे, जिनमें केवल 10 प्रतिशत औद्योगिक उपक्रम सम्मिलित थे। 4% प्रन्यास अत्यधिक लघु आकार के थे, जिनमें औसतन 5 या 6 उपक्रम सम्मिलित थे। बड़े आकार के प्रन्यास वस्त्र, धातु-शोधन, चीनी, रबड़, इन्जीनियरिंग आदि उद्योगों में स्थापित हुए थे। अप्रैल 1923 में जारी अधिसूचना द्वारा इन प्रन्यासों के अधिकार

और कर्तव्य भी निश्चित थे। सम्पत्ति के स्वामी के रूप में औद्योगिक प्रन्यासों की प्रसंविदा करने का अधिकार प्राप्त था। इन्हें सर्वोच्च आर्थिक परिषद से अधिकार-पत्र प्राप्त करना पड़ता था। जिसमें स्थिर एवं कार्यशील पूँजी का विवरण सम्मिलित होता था। प्रन्यास सक्रिय पूँजी रहन रखकर ऋण प्राप्त कर सकता था। वह ऋणपत्र जारी कर सकता था। कुल मिलाकर औद्योगिक प्रन्यासों का उद्देश्य व्यवसायिक सिद्धान्तों के अनुरूप योजना के लक्ष्यों की पूर्ति स्वीकार किया गया।

(4) मौद्रिक सुधार — नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत मौद्रिक लेन-देन पर आधारित बाजार-व्यवस्था पुनः स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य सामरिक साम्यवाद के दौरान अव्यवस्थित वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित करना तथा मुद्रा का स्थिरीकरण करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा सहायता प्राप्त उद्योगों की संख्या घटा दी गई, आलाभकारी उपक्रम बन्द कर दिए गए तथा स्थानीय बजटों को प्रादेशिक बजटों से अलग कर दिया गया। परन्तु इन उपायों से संघ सरकार के बजट घाटे में कमी नहीं आई थी तथा उसे प्रतिवर्ष वृद्धिशील मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करनी पड़ी। इससे कीमत-स्तर में भारी वृद्धि हुई है। सरकार को 1921-22 में दो बार मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। 1924 में पुरानी मुद्रा के ~~स्थान~~ स्थान पर नई

मुद्रा प्रचलित की गई, जिससे स्थिति में सुधार हुआ। 1923 में स्टेट बैंक का पुनर्गठन भी वित्तीय पुनर्गठन के उपायों में से एक था। स्टेट बैंक को कोषागार द्वारा 50 मिलियन रूबल प्रदान किए गए, ताकि वह औद्योगिक न्यासों को कार्यशील पूँजी उधार दे सके।

(5) आन्तरिक व्यापार की पुनर्जीवन — सामरिक साम्यवाद की नीति के अन्तर्गत इसे तीन उपायों से पुनर्जीवित किया गया —

(i) निजी व्यापारियों (नेपमैन) के विकास द्वारा

(ii) सहकारी समितियों को सहायता देकर, तथा

(iii) सिण्डीकेटों के निर्माण द्वारा।

फुटकर व्यापार के क्षेत्र में 'नेपमैन (Nepmen) नामक गैर-सरकारी व्यापारी का आविर्भाव हुआ। 1924 में 75 प्रतिशत फुटकर व्यापार तथा 20 प्रतिशत थोक व्यापार का संचालन निजी व्यापारी कर रहे थे। 1923 के बाद राजकीय एवं सहकारी संस्थाओं ने व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया तथा धीरे-धीरे उनका (आत्म-बल) बढ़ गया। औद्योगिक न्यासों ने थोक व्यापार के लिए सिण्डीकेटों का निर्माण किया। केन्द्रीय स्तर पर

सर्वोच्च आर्थिक परिषद् ने तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रादेशिक सरकारों ने थोक एवं फुटकर व्यापार के लिए कई समितियों का गठन किया गया। 1928 तक मिली व्यापारियों के हाथों में केवल 5 प्रतिशत थोक व्यापार तथा 23 प्रतिशत फुटकर व्यापार रह गया।

(6) अन्य नीतिगत परिवर्तन ⇒ नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत सामरिक साम्यवाद के दौरान बैंकों में व्यक्तिगत जमाराशियों पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए। निजी व्यक्तियों की बैंक जमाओं को करों से मुक्त कर दिया गया। सरकारी सट्टापत्रों और विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय हेतु व्यावसायिक केन्द्रों में विशेष एक्सचेंज खोले गए। रेलवे, डाकतार, तेल, विद्युत, जल आदि सेवाओं के मूल्य चुकाने की व्यवस्था की गई। 1924 में करों की पारस्परिक प्रणाली अपनायी गई। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पुनः करारोपण किया गया। सरकारी बजट से राजकीय संस्थाओं को बाहर कर दिया गया तथा सरकारी व्यय में मितव्ययता द्वारा बजट का घाटा दूर करने का प्रयास किया गया।

वस्तुतः नवीन आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप रूस में जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली विकसित हुई, वह संक्रमणकालीन मिश्रित 'अर्थव्यवस्था' थी। इसमें पूँजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के लक्षण विद्यमान थे। यदि उद्योग

एवं थोक व्यापार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता थी तब कृषि एवं फुटकर व्यापार के अन्तर्गत निजी क्षेत्र का प्रभुत्व था। जून 1918 में गृह-युद्ध छिड़ने पर सोवियत सरकार को सामरिक साम्यवाद की नीति परिस्थितिवश अपनानी पड़ी थी। युद्धकाल में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, और श्रम) पर सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था।

परन्तु इस नीति के आर्थिक परिणाम अत्यन्त भयावह सिद्ध हुए। सामरिक साम्यवाद के विनाश ने सिद्ध कर दिया कि पूँजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था में संक्रमण, जिसके लिए संस्थागत ढाँचे में परिवर्तन आवश्यक होता है। धीरे-धीरे ही सम्भव है। मार्च 1921 में बोल्शेविक पार्टी की दसवीं बैठक में स्वयं लेनिन ने स्वीकार किया था, हम किसानों और श्रमिकों की प्रमुख उत्पादक शक्तियों की विफलता एवं विनाश, अत्यधिक थकावट एवं बलहीनता की ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ कुछ समय के लिए सभी विचारों को वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के मौलिक विचार अधीन कर दिया जाना चाहिए। नवीन आर्थिक नीति ऐसी मौलिक विचार को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास थी। इसलिए नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत असंख्य छोटे-छोटे औद्योगिक उपक्रमों का अराष्ट्रीयकरण किया गया कृषि एवं उद्योग के बीच विनिमय-व्यवस्था पुनः स्थापित की गई तथा फुटकर व्यापार के क्षेत्र में निजी व्यापारियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई।